रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

शिमला, मंगलवार, 27 सितम्बर, 1988/5 आश्विन, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार एवं मुद्रण विभाग

अधिसूचनाए

शिमला-2, 6 अगस्त, 1988

संख्या श्रम (1) 9/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, उद्योग विभाग की अधिसूचना सं0 आई0 एण्ड एस0-15 (ईस्ट) 489/59, दिनांक 1 मार्च, 1966 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग वर्ग-II राजपत्रित सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम सहर्ष बनाते हैं, अर्थात:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules shall be called the Himachal Pradesh Labour and Employment Department Class-II (Gazetted) Services Recruitment and Promotion (3rd Amendment) Rules, 1988.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Proforma.*—For the existing entries in Columns 1,2,6,7 and 11 in proforma of Himachal Pradesh Industry Department Class-II Gazetted Services Recruitment and Promotion Rules, 1966, the following entries shall *be substituted* namely :—

Column 1.—Employment Market Information Officer/Deputy Chief, University Employment and Guidance Bureau/Officer Incharge (Placement) Physically Handicapped/State Vocational Guidance Officer/Regional Employment Officers.

Column 2.—7 (Seven) (1/1/1/1/3 posts).

Column 6.—35 years and below.

Note-1.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange, as the case may be.

Column 7.—Deleted.

Column—11.—By promotion from amongst the District Employment Officers with 3 years regular or regular combined with *ad hoc* (rendered upto 31-12-1983) service in the grade.

शिमला-2, 25 अगस्त, 1988

सं0 4-6/87-एल0 ई0 पी0-वाल्यूम-IV.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या 4-6/82-श्रम-II, दिनांक 7 सितम्बर, 1987 के क्रम में और हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 (1970 का 10) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी भारतीय खाद्य निगम की संस्थापनाओं को, हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के उपबन्धों के प्रवर्तन से एक वर्ष की अवधि के लिये छूट देते हैं।

2. यह छूट तारीख 7-9-1988 से लागू होगी।

3. अंग्रेज़ी अनुवाद संलगित है।

[*Authorised English text of this department notification No.* 4-6/87-*LEP-Vol.-IV, dated the* 25*th August*, 1988, *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

Shimla-2, *the* 25*th August*, 1988

No. 4-6/87-LEP-Vol.-IV.—In contiuation of this department notification No. 4-6/82-Shram-II, dated the 7th September, 1987, and in exercise of the powers vested in him under section 27 of the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (Act No. 10 of 1970), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to grant exemption for a period of one year to all establishments of the Food Corporation of India located in Himachal Pradesh from the operation of the provisions of clause (*b*) of the proviso to sub-section (2) of section 7 of the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 in the public interest.

2. This shall come into force with effect from 7-9-1988

शिमला-2, 8 सितम्बर, 1988

संख्या 2-22/85-श्रम.—हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम (सीमित) की सेवाएं, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची में आती हैं;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि उक्त सेवाओं को, लोकहित में छः मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया जाए।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (एन) के उप-खण्ड (VI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति (सीमित) की सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोकहित में, छः मास की अवधि के लिये लोक उपयोगी सेवा के रूप में तत्काल घोषित करते हैं ।

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government notification No.* 2-22/85-*Shram, dated* 8-9-88 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

Shimla-2, *the* 8*th September*, 1988

No. 2-22/85-Shram.—Whereas the services of the Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation Ltd. falls in the First Schedule of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. XIV of 1947);

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the aforesaid services be declared as public utility service in the public interest for a period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (*vi*) of clause (*n*) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare the services of the Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation Ltd. as public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with immediate effect.

By order,
G. S. CHAMBIAL,
Commissioner-cum-*Secretary*.

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 सितम्बर, 1988

संख्या विद्युत-छ (5)-43/84-II—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9) की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व्यास निर्माण बोर्ड जो कि भारत सरकार का एक अंग है, के अधिकारियों को, जो कि उप-मण्डल अधिकारी से नीचे की पंक्ति के न हों, सरकार द्वारा स्थापित अथवा व्यवस्थित तार के प्रयोजन के लिए, तार लाईन तथा खम्बे लगाने सम्बन्धी, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों/निबन्धनों के अधीन रहते हुए, 400 के0 वी डेहर-भिवानी ट्रांसमीशन लाईन बिछाने के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में से गुजरती है और ऊर्जा ट्रांसमीशन में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों और यन्त्रों का प्रयोग करने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में यथा विनिर्दिष्ट तार प्राधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करते हैं ।

2. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, निम्नलिखित और शर्तें/निर्बन्धन करते हैं —

(i) कि गैर-सरकारी भूमि केवल टावर/अवलंब (लाईन बिछाने के लिए) का निर्माण करने, लगाने या उन्हें खड़ा करने के लिए ही अर्जित की जाएगी और भू-स्वामियों को प्रतिकर का संदाय भू-अर्जन अधिकारी, बी० एस० एल० प्रोजैक्ट मण्डी द्वारा दिए गए या दिए जाने वाले पंचाट के अनुसार व्यास निर्माण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और यदि प्रतिकर भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन न्यायालय द्वारा बढ़ा दिया जाता है, तो उसका संदाय भी व्यास निर्माण बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा ;

(ii) कि टावर/अवलंब खड़ा करने के लिए सरकारी भूमि केवल 99 वर्ष पट्टे के आधार पर ही अन्तरित की जाएगी;

(iii) कि सरकारी/गैर-सरकारी भूमि से यथा स्थिति वृक्षों को गिराने की आवश्यक अनुज्ञा व्यास निर्माण बोर्ड द्वारा, भारत सरकार कृषि मन्त्रालय से प्राप्त की जाएगी ;

(iv) कि व्यास निर्माण बोर्ड द्वारा फलों वाले वृक्षों का वही प्रतिकर संदत्त किया जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित विभाग द्वारा इस निमित्त अवधारित किया जाए;

(v) पूर्वोक्त लाईन के लिए पी० टी० सी० सी० क्लीयरैंस, यदि पहले प्राप्त न की हो तो उसे व्यास निर्माण बोर्ड प्राप्त करेगा।

(3) यह अधिसूचना 24 जुलाई, 1984 से प्रवृत्त होगी और प्रवृत्त समझी जाएगी।

———— —

आदेश द्वारा,
बी० सी० नेगी,
मुख्य सचिव।

[*Authoritative English text of this department notification No. VIDYUT-CHH* (5) 43/84-*II, dated* 9-9-88 *as required under clause* (3) *of Artical* 348 *of the Constitution of India*].

M. P. P. AND POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th September, 1988

NO. VIDYUT-CHH (5) 43/84-II.—In exercise of the power conferred by section 51 of the Indian Electricity Act, 1910 (Act No. 9 of 1910) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to confer the powers of Telegraph authority as specified in the Indian Telegraphs Act, 1885 (Act No. 13 of 1885) subject to the conditions/restrictions imposed thereunder, with respect to placing of telegraph fines and posts for the purpose of the telegraph established or maintained by the Government on the officers, not below the rank of S. D. O's of the Beas Construction Board, a part and limb of the Central Government, for laying of 400 K. V. Dehar-Bhiwani Transmission line....appliances and apparatus for the transmission of energy as it passes through the territory of Himachal Pradesh.

2. The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to impose the following conditions/restrictions:—

(*i*) That the private land has to be acquired only for the construction/erection/placing of towers/supports for laying transmission line and the compensation will be paid to the land owners as per award made or to be made by the Land Acquisition Collector B. S. L. Project Mandi or the compensation, if any, enhanced by the Court(s) under the Land Acquisition Act, 1894, by the Beas Construction Board;

(*ii*) That the Government Land for erection of towers/supports only will be got transferred on 99 years lease basis;

(*iii*) That the necessary permission for felling of trees from Government/Private land, as the case may be will be obtained from the Ministry of Agriculture, Government of India by the Beas Construction Board;

(*iv*) That Beas Construction Board will pay compensation of fruit bearing trees as per assessment of the concerned Department of Himachal Pradesh Government; and

(*v*) P. T. C. C. clearance for the above line will be obtained by the Beas Construction Board, if not already obtained.

3. This notification shall and shall be deemed to have come into force with effect from 24th July, 1984.

By order,
B. C. NEGI,
Chief Secretary.

लोक सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 अगस्त, 1988

संख्या पब-12/74/71 (भाग-3).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 12-74-जी0ए0डी0-II (पब), दिनांक 18-4-1977 द्वारा अधिसूचित उप-निदेशक, लोक सम्पर्क (राजपत्रित) (प्रथम वर्ग) लोक सम्पर्क विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में तुरन्त संशोधन करते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग उप-निदेशक (राजपत्रित) (प्रथम वर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 1988 हैं।

(2) यह नियम तुरन्त प्रवृत होंगे।

2. संशोधन उपबन्ध-III संलग्न है।

ANNEXURE-III

Name of the post: Deputy Director (Public Relations) (Class-I)
Name of the Department: Public Relations, Himachal Pradesh

Rule No./ Col. No.	Existing Provisions	Provisions as approved by the Commission
1	2	3
2.	One	Five
3.	G. C. S. Class-II Gazetted	Class-I (Gazetted)
4.	Rs. 500—800	Rs. 1200—1850
7.	(*i*) Degree of a recognised University.	(*i*) Degree of a recognised University.
	(*ii*) About 5 year's journalistic experience in a newspaper or news agency of standing; or public relations work in a Publicity Organisation. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).	(*ii*) Degree or diploma in Journalism or Public Relations from a recognised University/Institution.
		(*iii*) Three years journalistic experience in a Newspapers or News Agency of standing or experience of publicity and or public relation work in a reputed publicity organisation.

1	2	3
		OR
	Desirable: (*i*) Knowledge of current affairs national and international as also about Public Relations work in the country as a whole in general and in Himachal Pradesh in particular.	(*i*) Degree of a recognised University.
	(*ii*) Experience of Administration of public Relations.	(*ii*) 5 years experienee in the field of Journalism/Public Relations in a responsible capacity in State/Central Government Department/Organisation or of equivalent level in a Public Sector Undertaking; (*i*) Knowledge of current affairs national and international and also about the Public Relations work in the country as a whole and in Himachal Pradesh in particular; (*ii*) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh. (*iii*) Experience of Administration in the field of Public Relations.
10.	By promotion failing which by direct recruitment.	100% by promotion, failing which by direct recruitment.
11.	From the next lower posts in the Department namely, Publicity officers and other equivalent posts (with about 3 years service in the grade).	By promotion from amongst District Public Relations Officers/Information Officers Class-II (Gazetted) in the pay scale of Rs. 825—1580 with at least six years regular service or regular combined with *ad hoc* service (rendered upto 31-12-83), failing which by transfer/deputation from Government of India/other State Governments holding equivalent posts in the Government failing both by direct recruitment.
12.	Class-II Departmental Promotion Committee.	DPC to be presided over by the Chairman of the Commission or a Member nominated by him.
13.	As required under the rules.	As required under the Law.

आदेश द्वारा,
महाराज कृष्ण काव,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।